to cut the mango tree and use the area for cultivation;

(b) if so, what are the reasons and problems of Mango growers for taking such a drastic decision to change the mango belt into farming area; and

(c) what steps has been taken by Government to save the mango belts in Uttar Pradesh and other parts of the country?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI ARIVIND NETAM): (a) Yes, Sir.

(b) The Mango orchards in the mango belt of Kakori Malihabad comprise mostly of aged trees which have declined in their productivity. *Apart from this, the orchards do not bear good* crop because of heavy infestation of pests and diseases, which are not easy to control due to large sized trees, over crowding in the orchards etc. As such the orchardists are probably opting for uprooting of these trees.

(c) The Central Government have been providing funds to the State Government for rejuvenation of old orchards of different fruit crops including mango in Uttar Pradesh and other parts of the country. In the new proposal the assistance is proposed to be the expanded to cover supply of planting material, demonstrations, training and plant protection etc.

Agreement with Israel on Agricultural Technology

2283. SHRI SURESH PACHOURI: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Israel has agreed to provide agricultural technology to India;

(b) if so, whether the delegation of Indian farmers visited Israel and on reciprocal basis farmers from Israel visited India;

(c) if so, whether any agreement has been reached on agricultural technology; and

(d) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI ARIVIND NETAM): (a) to (d) A Memorandum of Understanding between Israel and India is under discussion for strengthening mutually beneficial cooperation in the field of agriculture and related technology.

An Indian delegation comprising of 16 members including farmers was sponsored by the National Horticulture Board to participate in the Agricultural Technology Exhibition (AGRITECH) held in Tel Aviv from 2nd to 6th May, 1993. In addition, several hundred Indian farmers visited the exhibition both individually and in groups. Government of India has not received any delegation of farmers from Israel.

उर्वरकों पर राज सहायता

2284. डॉ० जितेन्द्र कुमार जैन :
श्री राम जेठमलानी :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार द्वारा छोटे और सीमांत किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए वित्तीय वर्ष, 1992-93 के लिए उर्वरकों इत्यादि पर राज सहायता प्रदान करने के लिए 500 करोड़ रूपये की भारी राशि आबंटित की गयी थी;

(ख) यदि हां, तो किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए 31 मार्च, 1993 तक यह समस्त धन-राशि खर्च कर दी गयी थी;

(ग) यदि नहीं, तो कुल कितनी धनराशि खर्च की गयी थी और कितनी धनराशि शेष बच गयी थी;

(घ) किसानों के लाभ के लिए उपलब्ध करायी गई समस्त धनराशि को खर्च न करने के क्या कारण थे; और

(ङ) इस प्रयोजन के लिए खर्च की गई धनराशि से राज्य-वार कितने-कितने किसान परिवारों को लाभ हुआ था?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविंद नेताम): (क) से (घ) अनियंत्रित उर्वरकों को रियायत पर बेचने के लिए सरकार ने 340/- करोड़ रूपए की सहायता दी । इस योजना में छोटे/सीमान्त किसानों सहित सभी किसान शामिल हैं । राज्य सरकारों को इसकी पूरी रकम निर्मुक्त की गई थी ।

छोटे/सीमान्त किसानों के लाभ से सम्बद्ध कार्यक्रमों की बुनियादी सुविधाओं के लिए 500 करोड़ रूपए की अतिरिक्त राशि की घोषणा की गई थी । इनमें से, वित्त मंत्रालय की स्वीकृति के अनुसार, 31 मार्च, 1993 तक 362.06 करोड़ रूपए की राशि राज्य सरकारों को उपलब्ध कराई गई है ।

(ङ) आधारभूत संरचना विकास की स्कीमें स्थानीय क्षेत्र की आवश्यकताओं के आधार पर आरम्भ की जाती हैं इसलिए इन निधियों का संवितरण अलग-अलग लाभानुभोगियों को नहीं किया गया था ।

चावल और गेहूं के उत्पादन की तुलनात्मक दर

2285. श्री राम जेठमलानी :
श्रीमती सुषमा स्वराज :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि देश में गत दशक में चावल के

उत्पादन की दर में गेहूं के उत्पादन की दर से कम वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो 1980 के दशक के लिए दोनों खाद्यान्नों की उत्पादन दरों में वृद्धि संबंधी तुलनात्मक आंकड़े क्या है;

(ग) 1990 के दशक के आरम्भ में कुल कितनी कृषि भूमि पर धान की खेती की जाती थी तथा इसमें से कितने प्रतिशत भूमि सिंचित, वर्षा पर आधारित और असिंचित थी और दोनों खाद्यान्नों की प्रति हेक्टेयर औसत उत्पादन दरें क्या-क्या थीं ;

(घ) क्या यह भी सच है कि यह अनुमान है कि इस शताब्दी के अन्त तक देश को 105 मिलियन टन चावल की आवश्यकता होगी; और

(ङ) यदि-हां, तो उपर्युक्त आवश्यकता को पूरा करने के लिए आगामी वर्षों में उत्पादन की दर में वृद्धि करने हेतु क्या वार्षिक लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविंद नेताम) : (क) जी, नहीं ।

(ख) 1980-81 तथा 1990-91 तक की अवधि के दौरान चावल और गेहूं के उत्पादन में संयुक्त वृद्धि दर क्रमशः 3.81 तथा 3.62 प्रतिशत प्रतिवर्ष देखने में आई है ।

(ग) भू-उपयोग आंकड़े 1989-90 (नवीनतम उपलब्ध) के अनुसार चावल के अंतर्गत कुल सिंचित क्षेत्र देश भर में चावल के अंतर्गत 42.14 मिलियन हैक्टेयर क्षेत्र का 45.2 प्रतिशत था ।

चावल सहित विभिन्न फसलों की पैदावार के आंकड़े, सिंचित और असिंचित दोनों वर्गों के लिए सभी राज्यों/संघ शासित प्रदेशों द्वारा अभी संकलित नहीं किए जा रहे है । वैसे, 1990-91 के लिए सिंचित और असिंचित खरीफ चावल की पैदावार के कुछ मुख्य उत्पादक राज्यों से प्राप्त, नवीनतम उपलब्धि, अनुमान इस प्रकार हैं :

पैदावार के अनुमान

(किलोग्राम प्रति हेक्टेयर)

राज्य	सिंचित	असिंचित
असम	2274	965
बिहार	1225	897
कर्नाटक	2464	1604
मध्य प्रदेश	1643	1065
पंजाब	3240	2025
तमिल नाडु	3718	1216

(घ) और (ङ) आठवीं पंच वर्षीय योजना के अंतिम वर्ष 1996-97 के लिये चावल उत्पादन का 88.00 मिलियन मीटरी टन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है । चावल की आवश्यकता पूरी करने के लिए आठवीं पंच वर्षीय योजना के दौरान 3.95 प्रतिशत की उत्पादन वृद्धि दर लक्षित है ।

National Institute of Disaster Management for Hyderabad

2286. DR. NARREDDY THULASI REDDY:
DR. YEAMANCHILI SIVAJI :

Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state :

(a) whether there is any proposal from Andhra Pradesh to locate National Institute of Disaster Management at Hyderabad;

(b) if so, what are the details in this regard; and

(c) at what stage of consideration is the same ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI ARVIND NETAM) : (a) to (c) In view of the expertise available in the State in dealing with various natural calamities and the fact that Hyderabad has become an important centre for training and research, the Government of Andhra Pradesh have offered suitable land to locate the National Institute of Disaster Management at Hyderabad. The proposal is under consideration.

Agricultural Development Projects

2287. SHRIMATI SATYA BAHIN :
DR. SHRIKANT RAMCHANDRA JICHKAR :

Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state :

(a) what are the projects being undertaken under the World Bank financing Agricultural Development Projects in the near future;

(b) whether any project from Maharashtra is being taken up;

(c) if so, what is the nature and extent of this project; and

(d) if not, what are the reasons therefor ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF NON-CONVENTIONAL